



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I-खण्ड 1

PART I-Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 107]

No. 107]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 18, 2007/चैत्र 28, 1929

NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 18, 2007/CHAITRA 28, 1929

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

प्रारम्भिक जांच अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 अप्रैल, 2007

विषय : चीन, हाँगकाँग और जापान के मूल से अथवा वहाँ से निर्यातित "विटामिन बी₁₂ और उसकी व्युत्पत्तियों" के आयात के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरुआत।

सं. 14/12/2006-डीजीएडी.- सीमाशुल्क टैरिफ (संशोधन) अधिनियम, 1995 तथा सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं वसूली तथा क्षति निर्धारण) नियमावली 1995 को ध्यान में रखते हुए मै0 वोक्हार्ड लि., मुम्बई और मै0 मेरिड लि., मुम्बई ने निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें एतद् पश्चात् प्राधिकारी कहा जाएगा) के समक्ष चीन जन गण, हाँगकाँग और जापान के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित विटामिन बी 12 और उसके व्युत्पत्तियों के पाटन का आरोप लगाते हुए एक याचिका दायर की है और पाटनरोधी जांच शुरू करने और पाटनरोधी शुल्क लागू करने की सिफारिश की है।

1. विचाराधीन उत्पाद

वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद विटामिन बी 12 और उसकी व्युत्पत्तियाँ हैं (जिन्हें संबद्ध वस्तु भी कहा गया है) हायड्रोक्सीबालमिन तथा मेकोबालमिन अथवा मिथाइलोकोबालमिक विटामिन बी 12 की दो ज्ञात व्युत्पत्तियाँ हैं। यह उत्पाद कैल्शियम कार्बोनेट, डीसीपी, मैनिटॉल और जिलेटिन जैसे कैरियरों के संयोजन के साथ विटामिन बी 12 के विभिन्न सांद्रणों के रूप में बाजार में बेचा जाता है उत्पाद के दायरे में विटामिन बी 12 के सभी सांद्रण और उसकी व्युत्पत्तियाँ शामिल हैं। तथापि विटामिन बी 12 और उसकी व्युत्पत्तियाँ को अनेक समानार्थक नामों से जाना जाता है।

तथापि अप्रसंस्कृत अथवा अर्द्ध-परिष्कृत विटामिन बी 12 जिसे विटामिन बी 12 द्रव्य भी कहा जाता है को विचाराधीन उत्पाद के दायरे में शामिल नहीं किया गया है। विटामिन बी 12 के उत्पादन में विटामिन बी 12 द्रव्य (मध्यवर्ती) का उत्पादन भी शामिल होता है, जिसको आगे और प्रसंस्कृत करके क्रिस्टल स्वरूप में विटामिन बी 12 का उत्पादन किया जाता है। इस प्रकार उत्पादित विटामिन बी 12 को या तो विटामिन बी 12 के रूप में बेचा जाता है अथवा उसको आगे और प्रसंस्कृत करके विभिन्न सांद्रणों अथवा व्युत्पत्तियों पर आधारित पशु फीड ग्रेड के उत्पाद तथा खाद्य ग्रेड ट्राइट्यूरेट्स बनाए जाते हैं। इन फीड एवं खाद्य संयोजनों की तुलना में जो और कुछ नहीं बल्कि विभिन्न सांद्रणों में आगे और प्रसंस्कृत विटामिन बी 12 ही होते हैं, व्युत्पत्तियों हेतु अधिक लम्बी रासायनिक प्रक्रिया होती है। विटामिन बी 12 को व्युत्पत्तियों में परिवर्तित करने के लिए कुछेक संवृद्धिकारी उत्पादन प्रक्रिया, अतिरिक्त निविष्टियाँ, संयंत्र एवं उपकरण की आवश्यकता होती है। इससे उत्पाद के आधारभूत गुणधर्म में कोई परिवर्तन नहीं आता है।

विटामिन बी 12 का उपयोग प्रमुखतः विटामिन बी 12 की कमी का उपचार करने के लिए किया जाता है। ओरल बी 12 घातक रक्ताल्पता के उपचार में प्रभावी है। संबद्ध उत्पाद को आईटीसी(एचएस) उपशीर्ष 293626 के तहत वर्गीकृत किया गया है। तथापि यह सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और किसी भी प्रकार से वर्तमान जांच के कार्यक्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है।

2. घरेलू उद्योग की स्थिति

वर्तमान याचिका मै0 वोक्हार्ड लि. तथा मै0 मेरिन्ड लि. द्वारा संयुक्त रूप से दायर की गई है। मै0 मेरिन्ड लि., के पास उत्पादन सुविधाएं हैं और वह अनन्य रूप से वोक्हार्ड के लिए उत्पादन करती है। मै0 मेरिन्ड लि. बाजार में विचाराधीन उत्पाद की बिक्री नहीं करती है। बिक्री संबंधी संपूर्ण कार्यकलाप वोक्हार्ड द्वारा किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त मेरिन्ड लि. और वोक्हार्ड लि. सहयोगी कंपनियाँ हैं जो खोरास्किवाला होल्डिंग्स और इनवेस्टमेंट प्रा. लि. के नियंत्रण में है। याचिकाकर्ताओं द्वारा किया जाने वाले उत्पादन का हिस्सा संबद्ध उत्पाद के भारतीय उत्पादन का 100% है। देश में विटामिन बी 12 के कोई अन्य ज्ञात उत्पादक नहीं हैं।

मै0 वोक्हार्ड ने जांच अवधि के दौरान संबद्ध देशों से अग्रिम लाइसेंस के तहत संबद्ध वस्तुओं का आयात किया है, जिसके खिलाफ याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि वह पहले ही वस्तुओं का निर्यात कर चुका है और निर्यात संबंधी अनिवार्यताओं को पूरा कर चुका है। प्राधिकारी का मानना है कि पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) में निर्धारित किए अनुसार उत्पादक द्वारा शुल्क मुक्त अग्रिम लाइसेंसों के तहत आयातित निविष्टियों का उपयोग केवल निर्यात प्रयोजनों हेतु किये जाने पर ही उत्पादक घरेलू उद्योग दर्जे के पात्र ठहरेंगे अन्यथा नहीं।

उपर्युक्त की जांच करने के पश्चात् प्राधिकारी यह निर्धारित करते हैं कि नियम (घ) के साथ पठित नियम 2 (घ) के अर्थों के भीतर याचिकाकर्ता, घरेलू उद्योग है और उपर्युक्त नियमों के नियम 5 के संदर्भ में याचिका मानदण्डों को पूरा करती है।

3. शामिल देश

वर्तमान जाँच में शामिल देश चीन जन-गण, हाँगकाँग और जापान (इन्हें एतद् पश्चात संबद्ध देश कहा जाएगा) है।

4. समान उत्पाद

याचिकाकर्ताओं ने दावा किया है कि उनके द्वारा उत्पादित वस्तु संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित वस्तुओं के समान वस्तु है। याचिकाकर्ता द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु और संबद्ध देशों द्वारा निर्यातित उत्पाद में कोई विशेष अंतर नहीं है। याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि दोनों तकनीकी एवं वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। याचिकाकर्ता ने डीजीसीआईएंडएस तथा आईबीआईएस (अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सूचना प्रणाली) द्वारा संकलित आयातों के संबंध में सौदेवार सूचना उपलब्ध कराई है और दावा किया है कि संबद्ध वस्तु तथा याचिकाकर्ता कंपनी द्वारा उत्पादित और आपूरित वस्तु को एक दूसरे के स्थान पर उपयोग में लाया जा रहा है। वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ याचिकाकर्ता कंपनी द्वारा उत्पादित वस्तु को उपर्युक्त नियमों के अर्थों के भीतर संबद्ध देशों से आयातित उत्पाद के समान वस्तु माना जा रहा है।

5. सामान्य मूल्य

याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि चीन जन गण को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश माना जाना चाहिए। याचिकाकर्ता ने निवेदन किया है कि बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में भुगतान की गई अथवा देय कीमत या बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में उत्पादन लागत संबंधी सूचना आसानी से उपलब्ध न होने के कारण भारत को एक उपयुक्त प्रतिनिधि देश माना जाना उचित होगा। याचिकाकर्ता ने एक उचित लाभ मार्जिन को शामिल करते हुए भारत में देश यथासमायोजित कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण किया है। इस कीमत का निर्धारण, बिक्री, सामान्य एवं प्रशासनिक व्ययों तथा उचित लाभ को शामिल करते हुए, भारत में संबद्ध वस्तुओं की उत्पादन लागत के आधार पर किया गया है।

याचिकाकर्ताओं ने संबद्ध जांचों में चीन जन गण के संबंध में सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए यूरोपीय संघ (ईयू) को एक उपयुक्त बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश/क्षेत्र मानने का सुझाव दिया है। अतः नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 7 के अनुसार चीन जन गण के संबंध में सामान्य मूल्य के निर्धारण के प्रयोजनार्थ ईयू को एक उचित बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश के रूप में चुनने की परिकल्पना की गई है। हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा, इस अधिसूचना में निर्धारित विशिष्ट समय सीमा के भीतर इस चयन की उपयुक्तता पर अपनी टिप्पणियाँ प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया गया है।

अन्य संबद्ध देशों के संबंध में, याचिकाकर्ता ने संबद्ध देशों के लिए बिक्री, सामान्य एवं प्रशासनिक ऊपरी व्ययों तथा उचित लाभ को शामिल करते हुए परिकल्पित उत्पादन लागत पर विचार करके हाँगकाँग और जापान में संबद्ध वस्तुओं हेतु सामान्य मूल्यों का दावा किया है। संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के लिए दावा किए गए सामान्य मूल्यों के पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं।

6. निर्यात कीमत

याचिकाकर्ता ने डीजीसीआईएण्डएस तथा आईबीआईएस द्वारा उपलब्ध कराए गए सौदेवार आयात आंकड़ों के आधार पर प्रस्तावित अवधि में भारत औसत आयात कीमत के रूप में संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं की निर्यात कीमत का दावा किया है। कारखाना द्वार निर्यात कीमत का निर्धारण करने के लिए समुद्री भाड़े, समुद्री बीमा तथा निर्यात के देश में अंतर्देशीय परिवहन, पत्तन हैंडलिंग और पत्तन प्रभार के आधार पर समायोजन का दावा किया गया था। संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं की निर्यात कीमत के पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं।

7. पाटन मार्जिन

कारखाना द्वार स्तर पर सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की तुलना की गई है, जिसमें प्रत्येक संबद्ध देश के संबंध में काफी पाटन मार्जिन प्रदर्शित होता है। माना जा रहा है कि इस बात के प्रथम दृष्टया साक्ष्य मौजूद हैं कि संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तुओं का सामान्य मूल्य कारखाना द्वार निर्यात कीमत से काफी अधिक है जिससे प्रथम दृष्टया यह संकेत मिलता है कि संबद्ध देशों से निर्यातकों द्वारा संबद्ध वस्तुओं का पाटन किया जा रहा है।

8. क्षति एवं कारणात्मक संबंध

याचिकाकर्ता ने घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति से संबंधित विभिन्न मानदण्डों के संबंध में सूचना उपलब्ध कराई है। संबद्ध देशों से आयातों की समग्र मात्रा में वृद्धि, कुल आयातों में संबद्ध देशों से आयातों के बाजार हिस्से में वृद्धि, अत्यधिक कीमत कटौती, कम कीमत पर बिक्री, कीमत हास, घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में गिरावट, लाभ में कमी, नकद लाभ, लाभ की स्थिति में लगाई गई पूंजी पर आय से अत्यधिक वित्तीय घाटे तक उत्पादन में गिरावट, क्षमता उपयोग, उत्पादकता आदि जैसे मानदण्डों से सामूहिक एवं संचयी रूप से प्रथम दृष्टया यह प्रदर्शित होता है कि घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है। वास्तविक क्षति के अलावा, घरेलू उद्योग ने इस आधार पर वास्तविक क्षति के खतरे का दावा किया है कि पाटित आयातों में वृद्धि की दर काफी अधिक है और आयातों से घरेलू उद्योग की कीमतों में अत्यधिक कमी हो रही है और आयात ऐसी कीमतों पर किए जा रहे हैं जिससे घरेलू उद्योग पर अत्यधिक हानिकारी प्रभाव पड़ रहा है।

9. पाटनरोधी जाँच की शुरुआत

निर्दिष्ट प्राधिकारी उपर्युक्त पैराग्राफों के मद्देनज़र संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव की जाँच करने के लिए पाटनरोधी जाँचों की शुरुआत करते हैं।

10. जाँच की अवधि (पीओआई)

वर्तमान जाँच के प्रयोजनार्थ जाँच की अवधि 1 जनवरी, 2006 से 31 दिसम्बर 2006 तक की है। तथापि क्षति जाँच की अवधि में 1 अप्रैल 2003 से जाँच अवधि के अंत तक की अवधि शामिल होगी

11. सूचना प्रस्तुत करना

संबद्ध देशों के निर्यातकों और भारत में इस जाँच से संबद्ध ज्ञात आयातकों को अलग से लिखा जा रहा है कि वे अपने संगत सूचना निर्धारित प्रपत्र में और निर्धारित ढंग से प्रस्तुत करें और निम्नलिखित पते पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को अपने विचारों से अवगत कराएं :-

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री,
वाणिज्य विभाग,
पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय(डीजीएडी)
भारत सरकार,
कमरा सं. 240,
उद्योग भवन, नई दिल्ली- 110011.

उपर्युक्त नियमावली के नियम 6(5) के अनुसार, निर्दिष्ट प्राधिकारी जाँचाधीन वस्तु के औद्योगिक प्रयोक्ताओं को तथा प्रतिनिधिक उपभोक्ता संगठनों को अवसर प्रदान कर रहे हैं कि वे पाटन, क्षति और कारणात्मकता के संबंध में जाँच से संगत सूचना उपलब्ध कराएं। कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी नीचे दी गई समय सीमा के भीतर जाँच से संगत अपने निवेदन कर सकता है।

12. समय सीमा

क) सामान्य समय सीमा

वर्तमान जाँच से संबंधित कोई सूचना प्राधिकारी के पास लिखित रूप में उपर्युक्त पते पर इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से चालीस दिनों के भीतर पहुँच जानी चाहिए। तथापि जिन ज्ञात निर्यातकों एवं आयातकों को अलग से लिखा जा रहा है, उन्हें अलग से लिखे गए पत्र की तारीख से चालीस दिनों के भीतर सूचना प्रस्तुत करना अपेक्षित है। यह नोट किया जाना चाहिए कि निर्धारित समय सीमा में विस्तार से संबंधित कोई अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा।

ख) बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश के चयन हेतु विशिष्ट समय सीमा

जाँच से संबंधित हितबद्ध पक्षकार यूरोपीय संघ के औचित्य पर अपने विचार प्रस्तुत कर सकते हैं जिसकी परिकल्पना इस प्रारंभिक अधिसूचना के पैरा 5 में यथाउल्लिखित चीन जन गण के संबंध में सामान्य मूल्य के निर्धारण के प्रयोजनार्थ एक बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के रूप में की गई है। ये टिप्पणियाँ इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो हफ्तों के भीतर प्रस्तुत कर दी जानी चाहिए।

13. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

नियम 6(7) के संदर्भ में निर्दिष्ट प्राधिकारी एक सार्वजनिक फाइल रखते हैं। कोई हितबद्ध पक्षकार उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है जिसमें अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों के अगोपनीय अंश रखे गए हैं।

14. असहयोग

यदि कोई हितबद्ध पक्षकार आवश्यक सूचना देने से मना करता है या उचित समय के भीतर अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जाँच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जाँच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केन्द्रीय सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

क्रिस्टी एल. फेर्नान्डेज, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)****INITIATION NOTIFICATION**

New Delhi, the 18th April, 2007

Subject : Initiation of Anti-dumping Investigations concerning import of "Vitamin B₁₂ and its derivatives" originating in or exported from China, Hong Kong and Japan.

No. 14/12/2006-DGAD.—M/s. Wockhardt Limited, Mumbai and M/s Merind Ltd, Mumbai have filed an application before the Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority) in accordance with the Customs Tariff (Amendment) Act, 1995 and Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 alleging dumping of Vitamin B₁₂ and its derivatives originating in or exported from China PR, Hong Kong and Japan and have requested for initiation of anti-dumping investigations and levy of anti-dumping duties.

1. PRODUCT UNDER CONSIDERATION

The product under consideration in the present investigation is Vitamin B₁₂ and its derivatives (also referred to as subject goods). Hydroxocobalamin and Mecobalamin or Methylocobalamin are the two known derivatives of Vitamin B₁₂. The product is sold in the market in various concentrations of Vitamin- B₁₂, generally by addition of carriers like Calcium Carbonate, DCP, Mannitol and Gelatin. The scope of the product includes all concentrations of Vitamin B₁₂ and its derivatives. However, Vitamin B₁₂ and its derivatives are known by a large number of synonyms.

However, unprocessed or semi-finished Vitamin B₁₂, also called Vitamin B₁₂ liquid has been excluded from the scope of the product under consideration. The production of Vitamin B₁₂ involves production of Vitamin B₁₂ liquid (intermediate), which is further processed to produce Vitamin B₁₂ in crystal form. Vitamin B₁₂ so produced may either be sold as Vitamin B₁₂ or further processed into animal feed grade products and food grade triturates based on different concentrations or derivatives. As

opposed to these feed and food additives that are nothing but Vitamin B₁₂ in different concentrations further processed, derivatives involve a little longer chemical process. Some incremental production process, additional inputs, plant & equipment are required for converting Vitamin B₁₂ in to derivatives, which does not alter the basic properties of the product.

Vitamin B₁₂ is primarily used in the treatment of Vitamin B₁₂ deficiency. Oral B₁₂ is effective for the treatment of pernicious anemia. The subject goods is classified under ITC (HS) subheading 293626. However, the Customs classification is indicative only and is in no way binding on the scope of the present investigation.

2. DOMESTIC INDUSTRY STANDING

The present petition has been jointly filed by M/s. Wockhardt Limited and M/s Merind Ltd. M/s Merind Ltd is the company holding production facilities and producing exclusively for Wockhardt. M/s Merind Ltd. does not sell the product under consideration in the market. Entire sales functions are carried out by Wockhardt. Further, Merind Ltd. and Wockhardt Ltd. are associate companies held by Khorakhiwala Holdings and Investments Pvt. Ltd. Production of the petitioners constitutes 100% of Indian production of subject product. There is no other known producer of Vitamin B₁₂ in the country.

M/s Wockhardt has imported the subject goods under Advance License from China PR during the investigation period and the petitioner has claimed that it has already exported the goods produced from the product under consideration and completed its export obligations. The Authority considers that inputs imported under Duty Free Advance Licenses when used for export purpose only will not disqualify the producers from domestic industry status as laid down under Rule 2(b) of AD Rules.

The Authority after examining the above, determines that the petitioners constitute domestic Industry within the meaning of the rule 2(b) read with 2(d) and the petitioners satisfy the criteria of standing in terms of Rule 5 of the Rules supra.

3. COUNTRIES INVOLVED

The countries involved in the present investigation are China PR, Hong Kong and Japan (hereinafter also referred to as subject countries).

4. LIKE GOODS

The petitioners have claimed that goods produced by it are like articles to the goods originating in or exported from subject countries. There is no

significant difference in the subject goods produced by the petitioner and those exported from subject countries. Petitioners claim that the two are technically and commercially substitutable. Petitioners have provided transaction wise information on imports as compiled by DGCI&S & IBIS (International Business Information System) and have claimed that the subject goods and goods produced and supplied by the petitioner company are being interchangeably used. For the purpose of present investigation, the goods produced by the petitioner company is being treated as Like Articles to the product imported from the subject countries within the meaning of the Rules supra.

5. NORMAL VALUE

The petitioners have claimed that China PR should be treated non market economy country. Petitioners have submitted that it would be appropriate to consider India as an appropriate surrogate country for the reason that information with regard to price paid or payable in market economy third country or cost of production in market economy third country is not readily available to them. Petitioners have determined normal value on the basis of price payable in India, duly adjusted to include a reasonable profit margin. This price has been determined on the basis of cost of production of subject goods in India, including selling, general & administrative expenses and reasonable profit.

The petitioners have suggested European Union (EU) as an appropriate market economy third country/territory for determining the normal value with respect to China PR in the subject investigations. In accordance with Para 7 to Annexure-I of the Rules, it is therefore envisaged to choose EU as an appropriate market economy Country for the purpose of establishing normal value in respect of the People's Republic of China. Interested parties are hereby invited to comment on the appropriateness of this choice within the specific time limit laid down in this notification.

With regard to other subject countries, petitioner has claimed normal values for the subject goods in Hong Kong and Japan considering constructed cost of production including selling, general and administrative overheads and reasonable profit for subject countries. There is sufficient evidence of the Normal values claimed for the subject goods from subject countries.

2140 GI/07-3

6. EXPORT PRICE

The petitioner has claimed export price of the subject goods from the subject countries as the weighted average import price in the proposed period, based on transaction wise import data provided by the DGCI&S IBIS. Adjustments have been claimed on account of ocean freight, marine insurance and inland transportation in the country of exports, port handling and port charges to arrive at ex-factory export price. There is sufficient evidence of the export price for the subject goods from the subject countries.

7. DUMPING MARGIN

Normal value and export price have been compared at ex-factory level, which shows significant dumping margin in respect of each of the subject countries. It is considered that there is, prima facie, evidence that the normal value of the subject goods in the subject countries is significantly higher than the ex-factory export price indicating, prima facie, that the subject goods are being dumped by exporters from the subject countries.

8. INJURY AND CAUSAL LINK

The Petitioners have furnished information on various parameters relating to material injury to the domestic industry. Parameters such as increase in the absolute volume of imports from the subject countries, increase in the market share of imports from the subject countries in total imports, significant price undercutting, underselling, price depression, decline in market share of the domestic industry, deterioration in profit, cash profits, return on capital employed from a situation of profits to significant financial losses, decline in production, capacity utilization, productivity, etc. collectively & cumulatively, prima facie, show that the domestic industry has suffered material injury. In addition to the material injury, the domestic industry has claimed threat of material injury on the ground that the rate of increase in dumped imports is substantial, and the imports are significantly undercutting the prices of the domestic industry, and the imports are entering at such a prices as to have significantly depressing effect on the domestic industry.

9. INITIATION OF ANTI DUMPING INVESTIGATIONS

The Designated Authority, in view of the foregoing paragraphs, initiates anti-dumping investigations into the existence, degree and effect of alleged dumping of the subject goods originating in or exported from the subject countries.

10. PERIOD OF INVESTIGATION (POI)

The Period of Investigation for the purpose of the present investigation is 1st January 2006 to 31st December 2006. However, the period for injury examination would cover periods from 1st April 2003 to the end of the POI.

11. SUBMISSION OF INFORMATION

The exporters in the subject countries and the importers in India known to be concerned with this investigation are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the Designated Authority at the following address

Ministry of Commerce & Industry,
Department of Commerce,
Directorate General of Anti Dumping & Allied Duties
(DGAD)
Government of India,
Room No. 240,
Udyog Bhavan, New Delhi – 1100 11.

As per Rule 6(5) of Rule supra, the Designated Authority is also providing opportunity to the industrial users of the article under investigation, and to representative consumer organizations who can furnish information which is relevant to the investigation regarding dumping, injury and causality. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation within the time limit set out below.

12. TIME LIMIT

a) General Time Limits

Any information relating to the present investigation should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days from the date of publication of this notification. The known exporters and importers, who are being addressed separately, are however required to submit the information within forty days from the date of the letter addressed to them separately. It may be noted that no request, whatsoever, shall be entertained for extension in the prescribed time limit.

b) . Specific time limit for selection of market economy country

Interested parties to the investigation may wish to comment on the appropriateness of the European Union, which, as mentioned in the Para 5 of this initiation notification, is envisaged as a market economy third country/territory for the purpose of establishing normal value in respect of the China PR. These comments must be submitted within two weeks from the date of publication of this notification.

13. INSPECTION OF PUBLIC FILE

In terms of Rule 6(7), Designated Authority maintains a public file. Any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by other interested parties.

14. NON -COOPERATION

In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Designated Authority may record findings on the basis of facts available and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

CHRISTY L. FERNANDEZ, Designated Authority